

केंद्र की टीम ने किया निरीक्षण, सौंपेंगे जिम्मेदारी

दैनिक भास्कर

08/11/09

अस्पतालों में ढेरों कमियां

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करने आई केंद्र की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कई कमियां उजागर हुई हैं...

भास्कर न्यूज, छिंदवाड़ा



दवाईयों की जांच करते डिप्टी फायनेंस कंट्रोलर राजेश कुमार।

कहीं डाक्टर तो कहीं कर्मचारी नदारद पाए गए। केंद्र की टीम ने शनिवार को उभेगांव, बिछुआ और लिंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। दोपहर

करीब एक बजे छिंदवाड़ा पहुंची टीम ने जिला अस्पताल में भी चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया।

ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण करने के बाद वहां से निकलते समय सर्जिकल वाई में स्टाफ नर्सों के लिए टायलेट की कमी उजागर होने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। अधिकारियों ने जन्ननी सुरक्षा में नकद की बजाए चेक से भुगतान पर प्रसन्नता जाहिर की। वहीं उन्होंने दवाईयों के दुरुपयोग न होने देने के लिए अधिकारियों को

समझाइश भी दी। निरीक्षण के दौरान भारत सरकार के डिप्टी फायनेंस कंट्रोलर राजेश कुमार एवं मप्र के प्रभारी डा एंटोनी के साथ सुश्री मोना गुप्ता, डा भागवत, डा आनंद बी त्रिपाठी, सौरभ, डा फरहीन की टीम थी।

टीम ने उप स्वास्थ्य केंद्र खूनाझिरकला में भी स्वास्थ्य सुविधाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उपलब्धि एवं मातृ शिशु मृत्यु दर की समीक्षा भी की। इस दौरान मोहखेड़ बीएमओ केएस बजाज, डीपीएम अविनाश त्रिपाठी सहित मैदानी अमला उपस्थित था।

सरकार से कहेंगे, मेडिकल कॉलेज बनाए

नई दिल्ली से आए भारत सरकार के उप लेखा नियंत्रण अधिकारी राजेश कुमार ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्र का नियंत्रण रहेगा। इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कॉमन रिव्यूमिशन के लिए 18 राज्यों को चुना गया है। जिसमें मप्र भी शामिल है। वे यह पता लगाने आए हैं कि मैदानी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गाइड लाइन सही चल रही है या नहीं। यह भी देखा जा रहा है कि सुधार की गुंजाइश कहां है? मप्र के प्रभारी एवं एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर डा. एंटोनी ने सामुदायिक निगरानी की आवश्यकता बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए ग्राम स्तर से लेकर ब्लाक और जिला स्तर के प्लान बुलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में बढ़ रहे मरीज जागरूकता का उदाहरण है। इस मसले पर वे भारत सरकार से चर्चा भी करेंगे कि जहां 300 से अधिक बेड हैं उसे मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। उन्होंने स्टाफ और डाक्टरों की कमी को लेकर चिंता भी जाहिर की। बातचीत के इस दौर में बैतूल में सक्रिय केजीएम वेलफेयर सोसायटी के कार्यो की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की सूची और जांच शुल्क की सूची सूचना पटल के रूप में चस्पता होनी चाहिए। इस दौरान सीएमएचओ डा जीसी चौरसिया, सिविल सर्जन डा पीके श्रीवास्तव एवं टीम के सदस्य उपस्थित थे।